3 आदिवासी समाज की संस्कृति से मेरा गहरा जुड़ाव



5 जनसेवा और राजनीतिक अनुभव के प्रतीक



7 चाँद से सीखिए: हर आकार में पूर्ण होने की कला



RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 23 प्रति सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ :

सत्ता और संगठन में सुरेश सोनी के दखल से संकट में पार्टी

कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को दरकिनार करने का रचा जा रहा षड़यंत्र

कवर स्टोरी



-विजया पाठक
एडिटर

मध्यप्रदेश का व्यापमं घोटाला देश के सबसे चर्चित परीक्षा एवं भर्ती घोटालों में शामिल रहा है। इस मामले ने न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कथित प्रभाव, सिफारिश तथा बिचौलियों की भूमिका को लेकर भी गंभीर बहस पैदा की। इसी विवाद के बीच आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी का नाम सामने आया। एक आरोपी मिहिर कुमार चौधरी के बयान में कथित सिफारिश का उल्लेख, पुलिस की ओर से आरोपों को प्रमाणित नहीं मानना और बाद में हाईकोर्ट में इस मामले पर चर्चा- इन तीनों पहलुओं ने विवाद को खासा महत्वपूर्ण बना दिया।



सुरेश सोनी का मोहन सरकार में दबदबा

मोहन सरकार में सुरेश सोनी का दबदबा बना हुआ है। व्यापमं के कई आरोपी सुधीर शर्मा, अजय मेहता, मिहिर चौधरी जैसे आरोपी सरकार का हिस्सा बनकर सरकार चला रहे हैं। घोटाले में शामिल होने के बावजूद सरकार में अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। इस पूरे खेल में सुरेश सोनी का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। यहां तक कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेताओं की सरकार में अनदेखी करने में भी सोनी का हाथ बताया जा रहा है।

मिहिर कुमार चौधरी के बयान से उठा विवाद

विवाद की एक प्रमुख कड़ी मिहिर कुमार चौधरी का बयान था। व्यापमं से जुड़े अपराध नंबर 15/2013 के मामले में मिहिर का बयान 22 नवंबर 2013 को दर्ज किया गया था। बाद में यही बयान सुरेश सोनी और तत्कालीन संघ प्रमुख केएस सुदर्शन से संबंधित विवाद की चर्चा का आधार बना।

(शेष पेज 2 पर)

सुशासन के संकल्प को मिल रही नई धार

गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंच रही सुशासन की सरकार, जनता से सीधे संवाद कर रहे विष्णुदेव साय

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने शासन और जनता के बीच संवाद को प्राथमिकता देते हुए जनसमस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि सुशासन केवल सरकारी कार्यालयों में बैठकर योजनाएं बनाने से नहीं आता, बल्कि जनता के बीच पहुंचकर उसकी समस्याएं सुनने और उनका समाधान सुनिश्चित करने से स्थापित होता है। इसी सोच के साथ शुरू किया गया 'सुशासन तिहार' गांव-गांव, द्वार-द्वार तक प्रशासन की पहुंच बढ़ाने और आम नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास मजबूत करने का माध्यम बना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कार्यशैली की विशेषता यह है कि वे जनसंवाद को प्रशासनिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत करना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेना और अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण के निर्देश देना इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है। वर्ष 2026 में सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश के सभी 33 जिलों और 146 विकासखंडों में प्रशासनिक दलों के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनने और उनके समाधान के प्रयास किए गए।



चौपाल से शासन तक पहुंच रही जनता की आवाज

मुख्यमंत्री साय की जनसंवाद शैली का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि वे ग्रामीणों के बीच सहज वातावरण में बैठकर उनकी समस्याएं सुनने पर जोर देते हैं। महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम कमरौद में बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित चौपाल इसका उदाहरण है। यहां उन्होंने ग्रामीणों से राशन, बिजली, प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन योजना जैसी सुविधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली। किसानों से भी बातचीत कर उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इस तरह की पहल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में सीबीआई की धमक:

समाज कल्याण घोटाले से लोहा चोरी तक, कई बड़े नाम जांच के घेरे में!

पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड समेत कई अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच ब्यूरो की सक्रियता ने प्रशासनिक और कारोबारी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। राज्य में दो चर्चित मामलों को लेकर जांच और संभावित कानूनी कार्रवाई पर निगाहें टिकी हुई हैं। पहला मामला समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजनों के नाम पर कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। दूसरा मामला भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े कथित लोहा चोरी और उससे संबंधित कारोबारी नेटवर्क की जांच का है। इन दोनों मामलों की प्रकृति अलग-अलग है, लेकिन इनके केंद्र में सरकारी व्यवस्था, निगरानी तंत्र और कथित अनियमितताओं की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। समाज कल्याण विभाग के मामले में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को लेकर चर्चा है, जबकि भिलाई में लोहा चोरी के प्रकरण में ट्रांसपोर्ट कारोबारी इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू और स्थानीय नेटवर्क की गतिविधियां जांच का विषय बताई जा रही हैं।

(शेष पेज 2 पर)

समाज कल्याण घोटाले से लोहा चोरी तक, कई बड़े नाम जांच के घेरे में!

(पेज 1 का शेष)

समाज कल्याण विभाग में 2020-21 में दिव्यांगों के नाम पर करीब एक हजार करोड़ की रकम की हुई थी हेराफेरी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच के निर्देश दिये थे, लेकिन तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने संदेहियों के साथ मिलकर अदालत में दलील दी थी कि राज्य में जांच एजेंसियां इस घोटाले की विवेचना करने में सक्षम हैं। यही नहीं कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड को राहत दिलाने के लिए कई रोडे भी अटकाये थे। यह भी बताया जाता है कि कानूनी दांव पेंचों का सहारा लेकर प्रभावशील आरोपियों ने अदालत से स्टे भी प्राप्त कर लिया था। इस दौरान दलील दी गई थी कि छत्तीसगढ़ राज्य में सीबीआई की एंट्री पर बैन है। हालांकि लंबी चली कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामला सौंप दिया था। सूत्र तस्दीक कर रहे हैं कि इसी माह चार्जशीट दाखिल किये जाने के आसार हैं। सीबीआई ने इसकी तैयारी भी कर ली है। यह भी बताया जाता है कि आरोपी बनाए गए ज्यादातर आईएएस अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि समाज कल्याण विभाग में पदस्थ आधा दर्जन से ज्यादा द्वतीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भी एजेंसी ने नामजद किया है।



हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद

समाज कल्याण विभाग के कथित घोटाले की जांच को लेकर न्यायिक स्तर पर भी विवाद सामने आया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने का प्रश्न उठा। उस समय राज्य सरकार की ओर से राज्य की जांच एजेंसियों की क्षमता और अधिकार क्षेत्र से संबंधित दलीलें पेश किए जाने की बात कही गई थी। सीबीआई की जांच को लेकर विवाद का एक प्रमुख पहलू राज्य में केंद्रीय एजेंसी की सहमति और अधिकार क्षेत्र से जुड़ा था।

पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड की भूमिका पर सवाल

इस प्रकरण में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड का नाम चर्चा में रहा है। उनके अलावा अन्य वरिष्ठ और सेवानिवृत्त अधिकारियों के नामों को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। इनमें सुनील कपूर, एमके राउत और डीएल अग्रवाल के नाम का उल्लेख भी सामने आया है। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम चर्चा में होना, जांच के दायरे में होना और औपचारिक रूप से आरोपी बनाया जाना अलग-अलग स्थितियां हैं। विवेक ढांड का शराब कारोबार से संबंधित कथित अनियमितताओं के आरोप भी शामिल हैं। इस आदिवासी बाहुल्य राज्य में आदिवासियों की कल्याणकारी योजनाओं का पैसा विवेक ढांड जैसे भ्रष्ट अफसर डकार जाते हैं। इन अफसरों ने भूपेश सरकार में जो भ्रष्टाचार किया है उसकी परतें खुलना चाहिए और अब ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ठोस एक्शन लेना चाहिए।

क्या इसी माह दाखिल होगी चार्जशीट?

मामले को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि सीबीआई आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है और इस प्रक्रिया के बाद कुछ वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।

भिलाई स्टील प्लांट में लोहा चोरी का मामला

सीबीआई की सक्रियता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े कथित लोहा चोरी प्रकरण से संबंधित है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में स्थानीय ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों और कारोबारियों की गतिविधियों की जांच की चर्चा है। आरोपों का केंद्र यह है कि औद्योगिक सामग्री की चोरी और उसके परिवहन या बिक्री में कथित तौर पर एक नेटवर्क सक्रिय हो सकता है।

गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंच रही सुशासन की सरकार, जनता से सीधे संवाद कर रहे विष्णुदेव साय

(पेज 1 का शेष)

आमतौर पर ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में जब प्रशासन स्वयं गांव तक पहुंचता है, तो लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी अधिकारियों के लिए भी यह संदेश है कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक मूल्यांकन कागजी आंकड़ों से नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाले लाभ से होना चाहिए।

किसान, महिला और गरीब परिवार सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में किसान, महिलाएं, गरीब परिवार और आदिवासी समुदाय सरकारी योजनाओं के प्रमुख लाभार्थी वर्गों में शामिल हैं। सरकार की ओर से कृषि, आवास, सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रमुख पहल है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये की दर तथा किसानों से धान खरीदी जैसे विषय भी सरकार की ग्रामीण और कृषि केंद्रित नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव लाभार्थियों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचने पर निर्भर करता है। साय सरकार की प्राथमिकताओं में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा



जाए। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

सुशासन तिहार बना जनविश्वास का माध्यम

सुशासन तिहार की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे केवल जनसभाओं और औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित रखने के बजाय शिकायतों और मांगों के निराकरण से जोड़ने का प्रयास किया गया है। शिविरों में ग्रामीण सड़क, पेयजल, बिजली, राशन, आंगनबाड़ी भवन, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और अन्य स्थानीय समस्याएं उठाते हैं। संबंधित विभागों को इन आवेदनों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी जाती है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम भीखमपुरा में आयोजित जनचौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह दृष्टिकोण बताता है कि जनसंवाद का उद्देश्य केवल लोगों की बातें सुनना नहीं, बल्कि उन पर प्रशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना भी है। हालांकि, ऐसे अभियानों की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि कितनी शिकायतों का वास्तव में समाधान हुआ, कितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिला और लंबित मामलों की संख्या कितनी कम हुई। नियमित निगरानी और कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक होने से इस पहल की विश्वसनीयता और बढ़ सकती है।

नेतृत्व की सहजता और प्रशासन की जवाबदेही

विष्णुदेव साय का राजनीतिक व्यक्तित्व उनकी सहजता, सरल संवाद शैली और ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में इन विशेषताओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलना उनके सामने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। गांवों में पहुंचकर लोगों की बात सुनना इस दिशा में सकारात्मक कदम है। लेकिन सुशासन की असली कसौटी केवल मुख्यमंत्री का जनता के बीच पहुंचना नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का संवेदनशील और जवाबदेह बनना है। यदि किसी गांव में पेयजल की समस्या उठाई जाती है, तो उसका स्थायी समाधान होना चाहिए। यदि किसी पात्र परिवार को आवास या राशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसकी पात्रता की जांच कर समय पर सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार किसानों की समस्याओं पर संवाद के साथ ठोस कार्रवाई भी जरूरी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई जनसंवाद की यह कार्यशैली तभी स्थायी परिणाम देगी, जब जिला प्रशासन से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित हो और शिकायतों के निपटारे की नियमित समीक्षा की जाए।

विकास और विश्वास की राह पर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जैसे भौगोलिक और सामाजिक विविधता वाले राज्य में शासन की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना आसान काम नहीं है। दूरस्थ गांवों, वन क्षेत्रों और आदिवासी बहुल इलाकों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति के साथ निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और सरकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति जानने की पहल को प्रमुखता दी है। यह उनकी सरकार की जनकेंद्रित कार्यशैली का महत्वपूर्ण पहलू है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस संवाद को नियमित प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान की प्रतीक्षा न करनी पड़े।

केन-बेतवा बचाओ आंदोलनः अमित भटनागर के आमरण अनशन से बढ़ी चिंता

-संवाददाता

जगत प्रवाह. पन्ना। केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहा चिता आंदोलन प्रभावित परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास के सवालों को लेकर चर्चा में है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन 27वें दिन में पहुंच गया था। रिपोर्ट में उनका वजन लगभग आठ किलो घटने की जानकारी भी दी गई थी। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि परियोजना से प्रभावित परिवारों का निष्पक्ष सर्वे कराया जाए, पात्र लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए। उनका कहना है कि विकास परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। केन-बेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल की समस्या कम करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, परियोजना के कारण विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। आंदोलन का आगे का रुख प्रशासन की कार्रवाई और प्रभावित परिवारों की मांगों पर होने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा।

मैं भी मांझी की बेटी हूं, आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं से मेरा गहरा जुड़ावः राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु



-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आदिवासी समाज की परंपरागत व्यवस्था सामाजिक एकता, न्याय, आपसी सहयोग और सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि समय के साथ शासन व्यवस्था, नीतियां और कानून बदलते रहते हैं, लेकिन आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं, सामाजिक नियमों और अलिखित संविधान को पीढ़ियों से जीवित रखा है। यह व्यवस्था समाज में सुख-शांति, प्रेम, सद्भाव और सामूहिकता बनाए रखने का महत्वपूर्ण आधार है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि देश में पहले राजाओं का शासन था, इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया और आज भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। समय के साथ शासन व्यवस्था और कानूनों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आदिवासी समाज की अपनी पारंपरिक व्यवस्था आज भी विद्यमान हैं जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है, लेकिन समाज के लोग पीढ़ियों से इसका पालन करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में लोग मिल-जुलकर पूजा-अर्चना करते हैं, विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं तथा सामूहिक रूप से पर्व-त्यौहार मनाते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने आदिवासी समाज की पारंपरिक न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि गांवों में मांझी और अन्य पारंपरिक प्रमुखों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। परिवारों के बीच विवाद, जमीन-जायदाद से संबंधित समस्याएं अथवा आपसी मतभेद होने पर लोग मांझी के पास जाते हैं। मांझी गांव के लोगों को एकत्रित कर सभी पक्षों की बात सुनते हैं और आपसी सहमति से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में गांव के प्रमुख व्यक्तियों और बुजुर्गों की सहभागिता से सामूहिक निर्णय लेने की समृद्ध परंपरा रही है। इस व्यवस्था में पीड़ परगना और देश परगना जैसी पारंपरिक संस्थाओं का भी विशेष महत्व रहा है। गांव स्तर पर समाधान नहीं होने पर समस्याओं को पीड़ परगना और आवश्यकता पड़ने पर देश परगना के समक्ष रखा जाता था। इस दौरान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को स्मृति चिह्न भेंट किया गया।



युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और लगन से साकार होगा विकसित भारत 2047 का संकल्पः मुख्यमंत्री धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिथौली, देहरादून स्थित यूपीईएस के 24वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के छह विद्यार्थियों को सिल्वर प्लेट पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। अब वे विश्वविद्यालय से निकलकर जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत, लगन और निरंतर सीखने की भावना आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपने परिश्रम और क्षमताओं के बल पर निर्धारित लक्ष्य हासिल करने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में अच्छे कार्य करने और दूसरों की सहायता करने से वास्तविक खुशी एवं संतुष्टि मिलती है। व्यक्ति की असली पहचान उसके व्यवहार, विनम्रता और संस्कारों से होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में सदैव सीखने की भावना बनाए रखने और अपने ज्ञान एवं क्षमताओं का उपयोग समाज तथा देश की प्रगति में करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीईएस ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय ने पिछले दो दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड को शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किया गया है। आधुनिक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों के समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दून विश्वविद्यालय में 'सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज' की स्थापना की गई है। यूपीईएस के 24वें दीक्षांत समारोह में इस वर्ष कुल 4,795 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। इनमें नियमित पाठ्यक्रमों के 3,806 विद्यार्थी तथा यूपीईएस ऑनलाइन के 989 विद्यार्थी शामिल हैं।

क्या व्यापमं घोटाले के आरोपी चला रहे हैं मोहन सरकार?

(पेज 1 का शेष)

मिहिर कुमार चौधरी ने अपने चयन के संबंध में प्रभावशाली लोगों से जुड़ी कथित सिफारिश का उल्लेख किया था। व्यापमं के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी के बयान में मिहिर को 'सोनीजी का आदमी' बताए जाने का उल्लेख था। यहीं से मामला राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया।

शिवराज ने सोनी के साथ किया धोखा, फिर सोनी ने शिवराज को लगाया ठिकाने

यह उस समय की बात है जब शिवराज मुख्यमंत्री थे और व्यापमं मामला चरम पर था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उस समय सुरेश सोनी की प्रदेश में तूती बोलती थी और शिवराज उनकी बात को टालते नहीं थे। सोनी की सिफारशों को प्रमुखता दी जाती थी। इसी बीच किसी सिफारिश पर शिवराज ने सुरेश सोनी का नाम आगे कर दिया। यह मामला सुर्खियों में आ गया और सुरेश सोनी का व्यापमं में नाम जुड़ गया। इसका असर यह हुआ कि सुरेश सोनी को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। इसके लिए सोनी ने शिवराज को जिम्मेदार ठहराया। इसकी कसक सोनी वर्षों तक अपने अंदर दबाए रखे रहे। 2023 में जब प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने की बात आयी तो सुरेश सोनी सबसे पहले व्यक्ति थे जो शिवराज के विरोध में खड़े हुए और अंततः मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गये।

कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री की रेस बाहर करने में सोनी का हाथ

सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि 2023 में प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाये जाने की रेस में पहले स्थान पर कैलाश विजयवर्गीय थे। इनके अलावा प्रहलाद पटेल, नरेन्द्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव के नाम की भी चर्चाएं थी। लेकिन बताया जाता है कि सुरेश सोनी, कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाये जाने के विरोध में थे। अब जब वह मोहन सरकार में मंत्री हैं तो यहां पर सोनी कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को दरकिनार करने का षड़यंत्र रच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दतिया विस के उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाने में भी सोनी का हाथ था। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा व्यापमं घोटाले के एकमात्र गवाह थे। सुरेश सोनी को घोटाले से बचाने के लिए शर्मा ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। हालांकि आज वह दुनिया में नहीं हैं लेकिन कहा जाता है कि उनकी मौत सामान्य नहीं थी बल्कि हत्या थी। कहीं न कहीं हत्या की साजिश उन्होंने ने ही रची होगी जो व्यापमं षड़यंत्र के हिस्सा रहे।

सोनी के कारण प्रदेश में भय-भ्रष्टाचार का माहौल बना

आज मोहन सरकार में भय-भ्रष्टाचार का माहौल खड़ा हो गया है। भ्रष्टाचार में नेताओं से लेकर अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों को मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा है। निश्चित है कि कहीं न कहीं भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को सुरेश सोनी का संरक्षण मिल रहा है। जबसे सोनी की प्रदेश में सक्रियता बढ़ी है तबसे प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार का दायरा बढ़ा है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा? यही है मामले की महत्वपूर्ण कड़ी

05 नवंबर 2014 का मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश इस विवाद को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सुरेश सोनी और केएस सुदर्शन से संबंधित विवाद क्राइम नंबर 15/2013 के मामले से जुड़ा था। यह मामला फूड इंस्पेक्टर और जूनियर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की परीक्षा से संबंधित था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह उन PMT मामलों से अलग था, जिनकी जांच उस समय हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही थी। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में मिहिर कुमार चौधरी के 22 नवंबर 2013 के बयान का भी उल्लेख था।

2015 में फिर चर्चा में आया नाम

विवाद का एक अन्य पहलू 2015 में सामने आया, जब व्यापमं के प्रमुख आरोपियों में शामिल सुधीर शर्मा से संबंधित आयकर विभाग की रिपोर्ट की चर्चा हुई। 2010 से 2013 के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और संघ से जुड़े लोगों के यात्रा तथा अन्य खर्चों के भुगतान का उल्लेख था। इन रिपोर्टों में सुरेश सोनी का नाम भी सामने आया।

सम्पादकीय

भारत-अमेरिका ट्रेड डील संभावनाओं के बीच कूटनीति की अग्निपरीक्षा

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर एक बार फिर उम्मीदें बढ़ी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का 20 से 22 अक्टूबर 2026 के दौरान भारत दौरा ऐसे समय में हुआ, जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिशें तेज हैं। मुंबई में भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ उनकी वार्ता में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग जैसे विषय प्रमुखता से सामने आए। रुबियो ने भी संकेत दिया कि समझौते के कुछ ही मुद्दे शेष हैं। ऐसे में यह दौरा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत-अमेरिका संबंधों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ वर्षों में व्यापक हुए हैं। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, रक्षा सहयोग, तकनीकी विकास और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के विविधीकरण को लेकर साझा हित रखते हैं। अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार निर्यात और निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराता है। सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद और सेवा क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति इस साझेदारी को विशेष महत्व देती है। इसलिए प्रस्तावित ट्रेड डील का प्रभाव केवल आयात-निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास पर भी पड़ेगा।

हालांकि, इस समझौते की राह आसान नहीं रही है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा अगस्त 2025 में भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए भारी शुल्क से व्यापारिक संबंधों में तनाव पैदा हुआ था। फरवरी 2026 में बनी रूपरेखा के तहत अधिकांश भारतीय वस्तुओं पर शुल्क दर 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने की बात सामने आई, लेकिन अंतिम समझौते को लेकर मतभेद बने रहे। भारत का जोर इस बात पर है कि उसके निर्यातकों को वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में नुकसान न उठाना पड़े। दूसरी ओर, अमेरिका भारतीय बाजार में अपने उत्पादों के लिए अधिक पहुंच चाहता है।

यही वह बिंदु है जहां भारत की आर्थिक कूटनीति की असली परीक्षा होती है। व्यापार समझौते का उद्देश्य केवल शुल्क कम करना नहीं, बल्कि दोनों देशों के लिए टिकाऊ और संतुलित आर्थिक व्यवस्था तैयार करना होना चाहिए। यदि भारत अमेरिकी वस्तुओं के लिए बाजार खोलता है, तो उसे अपने किसानों, छोटे उद्योगों, घरेलू विनिर्माताओं और सेवा क्षेत्र के हितों की भी रक्षा करनी होगी। कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रियायत देने से पहले उसके दीर्घकालीन परिणामों का आकलन आवश्यक है। समझौता तभी सफल माना जाएगा, जब उससे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े और देश के कमजोर आर्थिक वर्गों पर अनावश्यक दबाव न पड़े।

विदेशमंत्री मार्को रुबियो का दौरा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की संभावनाएं व्यापक हैं। रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग भारत के विकास को नई गति दे सकता है। हालांकि, इन संभावनाओं को वास्तविक उपलब्धियों में बदलने के लिए स्पष्ट नीतियों, निवेश की अनुकूल परिस्थितियों और दोनों पक्षों के बीच भरोसे की आवश्यकता होगी। भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी समझौते की घोषणा और उसका सफल क्रियान्वयन दो अलग-अलग बातें हैं। जल्दबाजी में किया गया समझौता अल्पकालीन राहत तो दे सकता है, लेकिन यदि उसमें घरेलू उद्योगों और दीर्घकालीन आर्थिक हितों की अनदेखी हुई, तो भविष्य में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसके विपरीत, अत्यधिक कठोर रुख भी निर्यातकों और निवेशकों के लिए अनिश्चितता बढ़ा सकता है। इसलिए व्यावहारिकता और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन जरूरी है।

सियासी गहमागहमी

क्या मप्र में फिर बढ़ रही है शिवराज की लोकप्रियता?

मध्यप्रदेश की राजनीति में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सक्रियता ने एक बार फिर उनके राजनीतिक प्रभाव को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज की पहचान केवल एक राजनेता की नहीं, बल्कि जनता के बीच 'मामा' के रूप में स्थापित नेता की रही है। महिलाओं, किसानों और ग्रामीण वर्गों के बीच उनकी लोकप्रियता उनकी राजनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण आधार रही है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भले ही उनकी राजनीतिक भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित हो गई हो, लेकिन मध्यप्रदेश से उनका जुड़ाव कम नहीं हुआ है। हाल के दिनों में सीहोर जिले के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों के घरों को हटाए जाने के मामले में उनका खुलकर सामने आना इस बात का संकेत है कि वे प्रदेश के जनसरोकारों से दूरी बनाने के पक्ष में नहीं हैं। किसानों की समस्याओं पर उनकी सक्रियता भी इसी कड़ी का हिस्सा है। हालांकि, इन घटनाओं को सीधे उनकी लोकप्रियता में निर्णायक वृद्धि का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि शिवराज की जनसंपर्क शैली और सहज राजनीतिक व्यक्तित्व आज भी उन्हें प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बनाए हुए हैं।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में उच्च स्तर पर फिर मिले बदलाव के संकेत

मध्यप्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। पार्टी के भीतर नई नियुक्तियों और जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण को लेकर चल रही कवायद संकेत दे रही है कि प्रदेश नेतृत्व अब संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने की तैयारी में है। आगामी विधानसभा चुनाव 2028 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के सामने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और सक्रिय नेताओं को आगे लाने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद संगठनात्मक फेरबदल की संभावनाओं ने पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, बदलाव की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस केवल चेहरों को बदलेगी या संगठन की कार्यशैली में भी वास्तविक परिवर्तन करेगी? हाल में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सिंह चौहान की पुनर्नियुक्ति से यह संकेत भी मिला है कि पार्टी नए चेहरों के साथ अनुभवी नेताओं पर भरोसा बनाए रखने की रणनीति अपना सकती है। कांग्रेस के सामने चुनौती गुटीय संतुलन साधने के साथ कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करने की भी है। संगठन में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधना आवश्यक है, लेकिन केवल पदों का बंटवारा पार्टी को मजबूत नहीं बना सकता।

हफ्ते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं।
अब जवाब देंगे। 1 नवंबर - चलो दिल्ली।
वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली। छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो जरूर आए।

-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi



जहाँ भाजपा वहाँ घोटाला। राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद भाजपा ने भगवान महाकाल के साथ घोटाला कर दिया है।
महाकाल लोक निर्माण के समय हुए घोटाले के बाद अब वहां हो रहे आयोजनों में भी भ्रष्टाचार किया गया है। फर्जी बिल लगाकर सरकारी धन भाजपा की जेब में जा रहा है।

-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

जनसेवा और राजनीतिक अनुभव के प्रतीक बृजमोहन अग्रवाल

समता पाठक/जगत प्रवाह



छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनका राजनीतिक जीवन जनसंपर्क, संगठनात्मक सक्रियता और प्रशासनिक अनुभव की लंबी यात्रा का उदाहरण है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राज्य की राजनीति से भारतीय संसद तक का उनका सफर निरंतर राजनीतिक सक्रियता का परिचायक है। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल का जन्म 1 मई 1959 को रायपुर में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.), अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (एम.ए.) तथा विधि स्नातक (एलएलबी) की शिक्षा प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विषयों को समझने की दृष्टि प्रदान की। विद्यार्थी जीवन से ही उनमें सामाजिक गतिविधियों और सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि विकसित हो गई थी।

अग्रवाल ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी राजनीति से की। वर्ष 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से वे छात्र राजनीति से जुड़े। इस दौरान उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों में भाग लिया और नेतृत्व क्षमता विकसित की। आगे चलकर वे भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय हुए तथा संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद वे पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव वर्ष 1990 में आया, जब वे अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए रायपुर से निर्वाचित हुए। उस समय वे राज्य के युवा विधायकों में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने लगातार चुनावी सफलता प्राप्त करते हुए अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की।

वर्ष 1990 के दशक में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उन्होंने नवगठित राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ सरकार में उन्होंने गृह, जेल, श्रम, लोक निर्माण, स्कूल शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा जल संसाधन जैसे विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ संभालीं। अलग-अलग विभागों में कार्य करने के कारण उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य के विकास से जुड़े विविध विषयों पर अनुभव प्राप्त हुआ। उनकी राजनीतिक पहचान केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं रही। वे विधानसभा में लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में सक्रिय रहे और रायपुर के रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से आठ बार विधायक निर्वाचित हुए। उनके लंबे विधायी अनुभव ने उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति के प्रमुख चेहरों में स्थापित किया।

बृजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक कार्यक्षेत्र रायपुर और आसपास के क्षेत्रों से गहराई से जुड़ा रहा है। संस्कृति और पर्यटन से संबंधित विभागों में उनके कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक विरासत और पर्यटन स्थलों को प्रोत्साहित करने से जुड़े प्रयासों को महत्व मिला। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संपर्क सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों को भी सार्वजनिक विमर्श में उठाते रहे हैं। रायपुर को शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की उनकी मंशा उनके सार्वजनिक वक्तव्यों में सामने आई है। हालांकि विकास संबंधी उपलब्धियों का मूल्यांकन संबंधित परियोजनाओं और आधिकारिक आँकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्ष 2024 में बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव में रायपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया और 18वीं लोकसभा के सदस्य बने। राज्य की राजनीति में कई दशकों का अनुभव लेकर संसद पहुँचना उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

कुलदीप सेंगर की पुस्तक संघर्ष से शिखर तक का विमोचन



-संतोष सिंह कुशवाह

जगत प्रवाह. ग्वालियर। लेखक कुलदीप सेंगर द्वारा ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉ. सतेंद्र गुरु के जीवन पर लिखी किताब संघर्ष से शिखर तकः एक अनकही दास्तां का विमोचन एक समारोह में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय भविष्य मंथन (रजि.) संस्था द्वारा किया गया। इसमें श्रीश्री 1008 महामंडलेश्वर संत रामदास जी महाराज दंदरौआ धाम एवं संत कृपाल सिंह महाराज विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर लेखक कुलदीप सेंगर ने बताया कि इस कृति में आचार्य डॉ. सतेंद्र गुरु जी के छात्र राजनीति से लेकर संजय विचार मंच के राष्ट्रीय दायित्वों, दस्यु समस्या पर की गई उनकी बेबाक खोजी पत्रकारिता को समेटा गया है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर, विधायक डॉ. सतीश सिकरवार, पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता, जीविवि के पूर्व कुलपति प्रो. पीएम बिसेन। अंत में आभार प्रदर्शन कुलदीप दुबे ने किया।

बिजली विभाग के नाम पर बिना आईडी कार्ड चेकिंग का मामला, पार्षद ने कनिष्ठ यंत्री को सौंपा पत्र

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। नगर में बिजली विभाग के नाम पर बिना वैध पहचान पत्र (आईडी कार्ड) के चेकिंग करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का मामला सामने आया है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 10 भैरू बाबा वार्ड के पार्षद पुनीत जायसवाल ने मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने और विभागीय कर्मचारियों के लिए हार्ड कॉपी आईडी कार्ड अनिवार्य करने की मांग की है। पार्षद पुनीत जायसवाल द्वारा सौंपे गए पत्र के अनुसार, नवरात्रि और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान नगर में बिजली विभाग की चेकिंग के नाम पर खुद को विभागीय कर्मचारी बताने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा नागरिकों के घरों और प्रतिष्ठानों में जाँच की शिकायतें मिल रही हैं। शुक्रवार को नगर के वार्ड क्रमांक 10 में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहाँ तीन व्यक्ति खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बता रहे थे। हालांकि, उनके पास कोई वैध विभागीय पहचान पत्र उपलब्ध नहीं था। जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने चेकिंग आदेश की प्रति



होने की बात कही। पार्षद ने पत्र में स्पष्ट किया कि केवल किसी आदेश की प्रति दिखाना किसी व्यक्ति की वास्तविक विभागीय पहचान की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार की लापरवाही से आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी या ठगी होने की गंभीर आशंका बनी रहती है। कोई भी असमाजिक तत्व फर्जी कर्मचारी बनकर घरों में प्रवेश कर सकता है।

वैश्विक ऊर्जा संकट?

पेट्रोल-डीजल निर्यात शुल्क में बड़ा उलटफेर



किशन भावनानी
एडवोकेट

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के ऊर्जा बाजार में इन दिनों युद्ध, तेल की आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सुरक्षा का ऐसा त्रिकोण बन रहा है, जिसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश पर भी पड़ सकता है। एक ओर पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव, दूसरी ओर सऊदी अरब के हवाई अड्डों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमलों की खबरें और तीसरी ओर भारत सरकार का पेट्रोल एवं डीजल निर्यात शुल्क में बदलाव,ये घटनाएं बताती हैं कि आज तेल केवल व्यापार की वस्तु नहीं,बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का महत्वपूर्ण आधार है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर की देर रात जारी आदेश के माध्यम से 16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.50 रूपए से बढ़ाकर 2.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया, जबकि डीजल पर लगने वाला शुल्क 16 रूपए से घटाकर 8.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया। यानि पेट्रोल पर शुल्क बढ़ाकर पांच गुना हुआ, लेकिन डीजल पर 7.50 रूपए प्रति लीटर की कटौती हुई। सवाल है कि इस विरोधाभासी फैसले के पीछे क्या अर्थशास्त्र है, विंडफॉल टैक्स आखिर क्या है और क्या इससे आम आदमी को राहत मिलेगी? इन सब बातों को हम नीचे सटीकता से पैराग्राफ वॉइस समझने की कोशिश करेंगे।

क्या दुनिया के तेल बाजार पर मंडरा रहा है संकट? इसको समझने की करें तो, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। यमन के हूती संगठन और सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच तनाव बढ़ने के साथ मिसाइलों और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई हैं। 15 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, यमन के अदन स्थित अल-मआशिक राष्ट्रपति परिसर के आसपास भी हमला हुआ। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है कि राष्ट्रपति भवन पर हमले की रिपोर्ट यमन के राष्ट्रपति परिसर से संबंधित है, न कि सऊदी अरब के राष्ट्रपति भवन से। वहीं, सऊदी अरब में हवाई अड्डों और सामरिक प्रतिष्ठानों पर हमलों तथा तेल सुविधाओं को लेकर खतरे की खबरों ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं। इस संकट का आर्थिक महत्व इसलिए अधिक है, क्योंकि सऊदी अरब वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। यदि तेल उत्पादन, रिफाइनरी संचालन, बंदरगाहों या समुद्री परिवहन में लंबे समय तक बाधा आती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर संकट और गंभीर हो सकता है। हालांकि, हमलों की खबरों का अर्थ यह नहीं है कि सऊदी अरब का पूरा तेल उत्पादन बंद हो गया है या दुनिया में तेल की तत्काल भारी कमी निश्चित है। वास्तविक असर हमलों की अवधि, क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठानों, वैकल्पिक आपूर्ति और तेल भंडारों पर निर्भर करेगा।भारत के लिए यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा होने पर आयात बिल, रुपये की विनिमय दर, परिवहन लागत और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।इसी पृष्ठभूमि में निर्यात शुल्क की नीति को सटीकता से समझना आवश्यक है।

विंडफॉल टैक्स क्या है? आसान भाषा में समझने की करें तो, विंडफॉल टैक्स का सामान्य अर्थ है असाधारण परिस्थितियों में कंपनियों को होनेवाले अप्रत्याशित अतिरिक्त मुनाफेपर लगाया जाने वाला कर। उदाहरण के लिए, युद्ध या आपूर्ति संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तेजी से बढ़ जाएं और किसी कंपनी को सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ मिलने लगे, तो सरकार उस अतिरिक्त लाभ के एक हिस्से पर कर लगाने का निर्णय ले सकती है।लेकिन भारत के मौजूदा मामले में तकनीकी अंतर समझना जरूरी है। पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लागू शुल्क को समाचारों में विंडफॉल टैक्स कहा जा रहा है, जबकि इसे विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा अन्य लागू उपकरों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक कंपनी के वास्तविक अतिरिक्त मुनाफे की गणना करके ही प्रति लीटर शुल्क लगाया जाए। वर्तमान व्यवस्था में निर्यात पर निर्धारित दर लागू होती है। सरल उदाहरण से समझिए,यदि कोई रिफाइनरी घरेलू बाजार में बेचने के बजाय विदेश में पेट्रोल बेचकर अधिक कमाई कर सकती है, तो सरकार निर्यात पर शुल्क बढ़ाकर उस विकल्प को कुछ महंगा बना सकती है। इससे घरेलू बिक्री और निर्यात के बीच आर्थिक संतुलनप्रभावित हो सकता है। हालांकि, केवल शुल्क बढ़ाने से कंपनियां अनिवार्य रूप से सारा ईंधन घरेलू बाजार में बेचेंगी,इसकी गारंटी नहीं होती; इसके लिए मांग, उत्पादन क्षमता, निर्यात अनुबंध और अन्य नियम भी महत्वपूर्ण हैं।

16 अक्टूबर से लागू नई दरों को समझने की करें तो पेट्रोल पर पांच गुना बढ़ोतरी, डीजल पर कटौती, केंद्र सरकार के नए आदेश के अनुसार पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में अलग-अलग बदलाव किए गए हैं। विवरण पुरानी दर नई दरपेट्रोल निर्यात शुल्क 0.50 रूपए /लीटर 2.50/रूपए लीटर डीजल निर्यात शुल्क 16/रूपए लीटर 8.50 रूपए / लीटर डीजल शुल्क में कमी- 7.50 रूपए /लीटर इसका अर्थ है कि पेट्रोल पर शुल्क में 2 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जबकि डीजल पर 7.50 प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसलिए इसे केवल कर बढ़ाने का फैसला कहना सही नहीं होगा, यह दोनों ईंधनों के लिए अलग-अलग दिशा में किया गया नीतिगत बदलाव है।पेट्रोल का शुल्क बढ़ने से विदेश में पेट्रोल बेचने की लागत बढ़ सकती है। दूसरी ओर, डीजल पर शुल्क घटने से उसके निर्यात पर पड़ने वाला कर-भार कम होगा। सरकार के आदेश में दोनों दरों में बदलाव किया गया है, लेकिन केवल इस आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सरकार ने पेट्रोल की घरेलू कमी की पुष्टि कर दी है या डीजल की आपूर्ति सटीकता से पूरी तरह सुरक्षित हो गई है।



सरकार विंडफॉल टैक्स क्यों लगाती है? तीन प्रमुख उद्देश्य को समझने की करें तो पहला उद्देश्य है घरेलू ऊर्जा सुरक्षा। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बहुत आकर्षक हों, तो कंपनियों के लिए निर्यात करना अधिक लाभकारी हो सकता है। निर्यात शुल्क इस लाभ को प्रभावित करके घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के सरकारी प्रयास का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, आपूर्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।दूसरा उद्देश्य है सरकारी राजस्व और सार्वजनिक खर्च। अतिरिक्त शुल्क से सरकार को राजस्व मिल सकता है, जिसे व्यापक बजटीय संसाधनों के हिस्से के रूप में सार्वजनिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि इस शुल्क से प्राप्त प्रत्येक रुपया सीधे पेट्रोल-डीजल की सब्सिडी में ही खर्च किया जाता है। तीसरा उद्देश्य है असाधारण लाभ और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन। जब संकट के कारण किसी क्षेत्र की कंपनियों को असामान्य लाभ मिलता है, तो सरकार कर नीति के जरिए उसका कुछ हिस्सा सार्वजनिक राजस्व में लाने की कोशिश कर सकती है। इससे आर्थिक असमानता घटाने में अप्रत्यक्ष सहायता मिल सकती है, लेकिन केवल विंडफॉल टैक्स से आर्थिक असमानता समाप्त नहीं होती।

15 दिन में समीक्षा: भारत की नीति कैसे काम करती है? हम इसको समझने की करें तो भारत ने जुलाई 2022 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों में तेजी के बीच पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर ऐसे शुल्कों का इस्तेमाल शुरू किया था। बाद में दरों में बदलाव हुए और 2024 में ये शुल्क हटाए गए। 2026 में ऊर्जा बाजार में नए उछाल के बीच निर्यात शुल्क फिर लागू किए गए। सरकारी पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ की दर-सारणी में विभिन्न तारीखों पर शुल्कों में हुए बदलाव दर्ज हैं। इन दरों की लगभग प्रत्येक पखवाड़े समीक्षा की जाती है। जो अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव, निर्यात की आर्थिक स्थिति और घरेलू ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर शुल्क घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। तेल पर्याप्त उपलब्ध होने पर शुल्क कम या शून्य किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई स्वतः लागू नियम नहीं है कि घरेलू आपूर्ति बढ़ते ही शुल्क अनिवार्य रूप से शून्य हो जाएगा। यह सरकार के निर्णय और लागू अधिसूचना पर निर्भर करता है।दुनिया के अन्य देशों ने भी ऊर्जा संकट के समय असाधारण लाभ पर कर लगाने के विभिन्न तरीके अपनाए हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन ने 2022 में तेल और गैस कंपनियों के असाधारण लाभ पर ऊर्जा लाभ लेवी लागू की थी। यूरोपीय संघ ने भी ऊर्जा क्षेत्र के कुछ अतिरिक्त लाभों पर अस्थायी योगदान की व्यवस्था की थी। इन नीतियों की दरें, कानूनी आधार और लागू क्षेत्र सटीकता से भारत की व्यवस्था से अलग हैं।

क्या आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर? इसको समझने की करें तो सरकार के इस बदलाव का सीधा दायरा निर्यात शुल्क है, घरेलू पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्वतः बदलाव नहीं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, घरेलू खपत के लिए लागू मौजूदा शुल्क दरों में इस आदेश से परिवर्तन नहीं किया गया है। इसलिए 16 अक्टूबर को निर्यात शुल्क बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आम नागरिक को पेट्रोल खरीदते समय तत्काल 2.50 रूपए अतिरिक्त देना पड़ेगा। इसी तरह डीजल निर्यात शुल्क घटने का अर्थ यह भी नहीं है कि पेट्रोल पंप पर डीजल 7.50 रूपए सस्ता हो जाएगा। फिर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव संभव हैं। यदि वैश्विक तेल कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो परिवहन, माल ढुलाई, विनिर्माण और खाद्य वस्तुओं की लागत पर दबाव पड़ सकता है। इसके विपरीत, यदि घरेलू आपूर्ति स्थिर रहती है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें घटती हैं, तो अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। अंतिम असर कर नीति के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमत, रुपये की स्थिति, रिफाइनरी लागत और घरेलू मूल्य निर्धारण पर निर्भर करेगा।

सऊदी अरब में उड़ानों पर रोक: युद्ध का असर हवाई यातायात तक को समझने की करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा संकट का प्रभाव हवाई यातायात पर भी दिखाई दे रहा है।16 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया ने रियाद,दम्माम और जेद्दा से आने-जाने वाली उड़ानों का निलंबन 20 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाया है। इंडिगो और अकासा एयर ने भी कुछ सऊदी मार्गों पर 17 अक्टूबर तक उड़ानों के निलंबन या रद्दीकरण की घोषणा की है। अन्य अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों ने भी अपनी उड़ानों के कार्यक्रम बदले हैं। यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है कि ये संबंधित एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए लिए गए परिचालन निर्णय हैं, इन्हें भारत सरकार द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई गई एक समान रोक कहना सही नहीं होगा।यात्रियों को हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी एयरलाइन से उड़ान की स्थिति की सटीकता से पुष्टि करनी चाहिए।

तेल की हर बूंद अब अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी है, आज की वैश्विक परिस्थितियां भारत को ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक लाभ और आम नागरिक के हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती दे रही हैं। पेट्रोल निर्यात शुल्क में पांच गुना वृद्धि और डीजल शुल्क में 7.50 रूपए प्रति लीटर की कटौती इसी बदलते आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा है। विंडफॉल टैक्स या निर्यात शुल्क अपने आप में न तो तेल संकट का पूर्ण समाधान है और न ही महंगाई से सुरक्षा की गारंटी। इसका महत्व इस बात में है कि सरकार बदलती परिस्थितियों में निर्यात और घरेलू जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए एक नीतिगत साधन इस्तेमाल कर रही है। यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है, समुद्री मार्ग बाधित होते हैं या ऊर्जा प्रतिष्ठानों को गंभीर नुकसान पहुंचता है,तो भारत के सामने आयात लागत और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में पर्याप्त रणनीतिक भंडार, विविध आयात स्रोत, सुरक्षित परिवहन मार्ग और पारदर्शी कर नीति पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होंगे। अंततः ऊर्जा सुरक्षा का असली पैमाना केवल यह नहीं कि सरकार कितना कर लगाती है, बल्कि यह है कि देश में ईंधन की उपलब्धता बनी रहे, कीमतों पर अनावश्यक दबाव न बढ़े और संकट का बोझ आम नागरिक पर न्यूनतम पड़े।

चाँद से सीखिए: हर आकार में पूर्ण होने की कला

आज की बात



प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक



शरद पूर्णिमा पर विशेष...

घटना-बढ़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी विशेषता और उपयोगिता बनाए रखना ही जीवन की वास्तविक सफलता है। चाँद कभी अधूरा नहीं होता, फिर हम खुद को अधूरा क्यों समझते हैं? जीवन की हर अवस्था की अपनी चमक है; सफलता पूर्ण होने की प्रतीक्षा में नहीं, वर्तमान को सार्थक बनाने में है। क्या कभी आपने चाँद से पूछा है कि वह हर रात अपना आकार क्यों बदलता है? कभी पूर्णिमा की रात आकाश में अपनी सुंदरता बिखेरता है, कभी आधा होकर भी आकर्षित करता है, तो कभी पतली-सी रेखा बनकर क्षितिज पर मुस्कुराता है। अमावस्या की रात हमारी आँखों से ओझल भी हो जाता है। लेकिन क्या चाँद अपने घटते आकार से निराश होता है? क्या वह पूर्णिमा की प्रतीक्षा में अपनी चमक और उपयोगिता छोड़ देता है? शायद नहीं! क्योंकि प्रकृति का यह अद्भुत शिक्षक हमें जीवन का एक गहरा रहस्य समझाता है- पूर्णता किसी एक अवस्था का नाम नहीं, बल्कि अपनी प्रत्येक अवस्था को सार्थक बनाने की कला है।

आकार बदलता है, अस्तित्व नहीं

भारतीय पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष में लगभग पंद्रह दिनों तक चंद्रमा का प्रकाशित दिखाई देने वाला भाग घटता है और शुक्ल पक्ष में क्रमशः बढ़ता है। विज्ञान बताता है कि इस दौरान चंद्रमा स्वयं छोटा-बड़ा नहीं होता, केवल सूर्य से प्रकाशित उसका दिखाई देने वाला हिस्सा बदलता है। यही जीवन का पहला सूत्र है। परिस्थितियाँ हमारी पहचान का बाहरी स्वरूप बदल सकती हैं, लेकिन हमारी वास्तविक क्षमता और मानवीय मूल्य उनसे निर्धारित नहीं होते। मनुष्य का जीवन भी चंद्रमा की कलाओं जैसा है। बचपन की अपनी विशेषताएँ हैं, युवावस्था की अलग संभावनाएँ और प्रौढ़ावस्था की अपनी गरिमा। कभी उपलब्धियाँ हमारे साथ होती हैं, कभी संघर्ष सामने खड़ा होता है। कभी संसाधन पर्याप्त होते हैं, कभी सीमित। लेकिन हम अक्सर वर्तमान को कमतर मानकर भविष्य की किसी काल्पनिक पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगते हैं।

अच्छी नौकरी मिलेगी, तब खुश रहेंगे। पर्याप्त धन होगा, तब समाज के लिए कुछ करेंगे। बड़ी पहचान बनेगी, तब अपनी प्रतिभा दिखाएँगे। परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, तब जीवन का आनंद लेंगे। हम भविष्य में पूर्ण होने की प्रतीक्षा करते-करते वर्तमान में उपलब्ध अपनी पूर्ण संभावनाओं को अधूरा छोड़ देते हैं।

हर कला का अपना सौंदर्य, हर उम्र का अपना सामर्थ्य

जरा चंद्रमा को देखिए। दूज का चाँद पूर्णिमा जितना उज्ज्वल नहीं होता, लेकिन उसका अपना आकर्षण है। चौथ का चंद्रमा श्रद्धा का केंद्र बनता है। अष्टमी का आधा चाँद भी आकाश की सुंदरता बढ़ाता है। पूर्णिमा की चाँदनी का अपना अनुपम सौंदर्य है। प्रकृति किसी एक कला को श्रेष्ठ और दूसरी को निरर्थक घोषित नहीं करती। फिर हम अपने जीवन की अलग-अलग अवस्थाओं को सफलता और असफलता के तराजू पर क्यों तौलते हैं? एक विद्यार्थी के पास अनुभव कम है, लेकिन सीखने की जिज्ञासा उसकी पूँजी है। युवा के पास धन सीमित हो सकता है, लेकिन ऊर्जा, समय और नए विचार उसकी शक्ति हैं। बुजुर्ग की शारीरिक क्षमता घट सकती है, लेकिन अनुभव, धैर्य और मार्गदर्शन का सामर्थ्य अमूल्य है। किसी का पद छोटा हो सकता है, लेकिन उसके कर्म का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि आज हमारे पास कितना है, बल्कि यह है कि जो उपलब्ध है, उससे हम कितना अच्छा कर सकते हैं।

दूसरों से प्रकाश लीजिए, पहचान अपनी बनाइए

चंद्रमा का एक और अद्भुत गुण है। वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। फिर भी उसकी चाँदनी कवियों की प्रेरणा, प्रेमियों की कल्पना और साधकों की आस्था बन जाती है। यह कितनी सुंदर सीख है! महान बनने के लिए प्रत्येक ज्ञान और गुण का मूल स्रोत स्वयं होना आवश्यक नहीं। माता-पिता से संस्कार, शिक्षकों से ज्ञान, मित्रों से सहयोग और अनुभवों से समझ प्राप्त करके भी हम अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं। सूर्य से प्रकाश लेकर भी चंद्रमा सूर्य की नकल नहीं करता। वह अपनी प्रकृति के अनुरूप दुनिया को एक अलग सौंदर्य देता है। मनुष्य को भी दूसरों से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी मौलिकता और विशेषता बनाए रखनी चाहिए।

अमावस्या अंत नहीं, नई शुरुआत का संकेत है

भारतीय संस्कृति में चंद्रमा शीतलता, सौम्यता और मन का प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा संयम और संतुलन की प्रेरणा देता है। हमारे मन की अवस्थाएँ भी चंद्रमा की कलाओं की तरह बदलती हैं। कभी आत्मविश्वास पूर्णिमा जैसा होता है, तो कभी निराशा अमावस्या जैसी। लेकिन अमावस्या चंद्रमा का अंत नहीं होती। उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष आता है और नई कलाएँ दिखाई देने लगती हैं। जीवन में भी कठिन समय अंतिम सत्य नहीं है। असफलता हमारी स्थायी पहचान नहीं है और सफलता ऐसा पड़ाव नहीं, जहाँ पहुँचकर प्रयास समाप्त कर दिए जाएँ।

शरद पूर्णिमा : शीतलता और अमृत का संदेश

25 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में चंद्रमा की आराधना और शीतलता का विशेष उत्सव है। लोकमान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। इसी आस्था से खीर को चाँदनी में रखने और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा जुड़ी है। यह अमृतवर्षा धार्मिक विश्वास है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं। इस उत्सव का जीवन-दर्शन भी सुंदर है। चंद्रमा की शीतलता हमें याद दिलाती है कि जीवन में केवल तेज और चमक पर्याप्त नहीं, व्यवहार में सौम्यता और संबंधों में मधुरता भी आवश्यक है। चंद्रमा की पूरी यात्रा हमें एक अंतिम संदेश देती है- पूर्णिमा बनने की आकांक्षा अवश्य रखिए, लेकिन दूज, चौथ और अष्टमी की अपनी विशेषताओं को कभी कम मत समझिए। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमेशा पूर्ण चाँद बनना नहीं, बल्कि अपनी हर कला में कुछ ऐसा कर जाना है, जिससे किसी और के जीवन में उजाला हो सके। याद रखिए, आपका आज चाहे जिस आकार में हो, उसमें चमकने की संभावना आज भी पूरी है।

कचरे के पहाड़ से बढ़ता प्रदूषण

पर्यावरण की फिक्र



डॉ. प्रशांत सिन्हा

पर्यावरणविद

शहरों की चमक के पीछे छिपा है एक काला सच और वह है कचरे के ऊँचे पहाड़। ये पहाड़ दूर से पहाड़ लगते हैं, पर असल में हमारी बदलती जीवनशैली, बढ़ती खपत और व्यवस्था की चूक के प्रतीक हैं। इनसे उठती दुर्गंध, जहरीली गैसें और धुआँ हमारी हवा, जमीन और स्वास्थ्य को लगातार जहर दे रहे हैं। आज के युग में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, उपभोग बढ़ रहा है और उसके साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। प्लास्टिक, खाद्य-अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कागज, कपड़े, निर्माण मलबा और खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट जो मिलकर शहरों के किनारे विशाल कचरे के ढेर बना रहे हैं। ये ढेर धीरे-धीरे पहाड़ जैसे ऊँचे हो जाते हैं और आसपास के इलाकों के लिए स्थायी खतरा बन जाते हैं। दिल्ली के ग़ाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला जैसे लैंडफिल साइट इस समस्या के स्पष्ट उदाहरण हैं। इन स्थलों पर वर्षों से जमा पुराना कचरा, अब विशाल कचरे के पहाड़ बन चुका है। ग़ाज़ीपुर स्थित कचरे के पहाड़ से उठने वाला धुआँ और दुर्गंध आसपास के निवासियों के जीवन को प्रभावित करती है। कचरे के पहाड़ों में जैविक कचरा बिना हवा के सड़ता है। इस प्रक्रिया से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दुर्गंधयुक्त गैसें निकलती हैं। मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, कचरे के ढेरों से निकलने वाला मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक गर्मी फैलाने वाला है। गर्मियों में इन कचरे के पहाड़ों में आग लगने की घटनाएँ आम हो जाती हैं। प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री के जलने से विषैला धुआँ फैलता है, जिसमें कणिकाएँ और हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं। ग़ाज़ीपुर में अप्रैल 2024 में लगी भीषण आग के बाद आसपास के लोगों ने आँखों में जलन, गले में खराश और साँस लेने में कठिनाई की शिकायत की थी। कचरे के पहाड़ों से केवल हवा प्रदूषित नहीं होती। बारिश के पानी से कचरे में मौजूद रसायन, भारी धातुएँ और सड़ने वाले पदार्थ मिलकर एक जहरीला तरल बनाते हैं, जिसे 'लीचेट' कहा जाता है। यह तरल धीरे-धीरे जमीन के भीतर घुसकर भूजल को दूषित कर देता है। जिन इलाकों में कचरा वर्षों से जमा है, वहाँ के आस पास के भूजल की गुणवत्ता खराब हो सकती है। दूषित जल से डायरिया, टाइफाइड, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा, जहरीले तत्व मिट्टी में मिलकर उसकी उर्वरता नष्ट कर देते हैं, जिससे पेड़-पौधे सूखने लगते हैं और कृषि योग्य भूमि बेकार होने लगती है। कचरे के पहाड़ों के निकट रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। लगातार दुर्गंध, धूल, धुआँ और विषैली गैसों के संपर्क में रहने से श्वसन रोग, दमा, आँखों की जलन, सिरदर्द, एलर्जी और त्वचा रोग बढ़ते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन संबंधी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। इस समस्या के लिए केवल नगर निगम या सरकार को दोष देना पर्याप्त नहीं है। हम सब भी इसके उत्तरदायी हैं। अनावश्यक प्लास्टिक का उपयोग, एक बार उपयोग होने वाली वस्तुएँ, खाद्य पदार्थों की बर्बादी और कचरे का मिश्रित रूप से फेंका जाना इस संकट को बढ़ाते हैं। नगर निकायों को व्यवस्थित कचरा संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। कचरे के पहाड़ों को केवल ढकना पर्याप्त नहीं है; उनका वैज्ञानिक तरीके से बायो-माइनिंग, पुनःचक्रण और पुनर्वास आवश्यक है। इसके अलावा हर घर में गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग-अलग कूड़ेदानों में रखा जाए। सब्जियों के छिलके, फलों के अवशेष और अन्य जैविक कचरे से घर पर या समुदाय स्तर पर खाद बनाई जाए। प्लास्टिक थैलियों, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक और अनावश्यक पैकेजिंग का उपयोग कम किया जाए। पुराने कपड़े, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर को फेंकने के बजाय दोबारा उपयोग या रीसाइक्लिंग के लिए दिया जाए। नगर निगम द्वारा दरवाजे पर कचरा संग्रहण, कचरा प्रसंस्करण संयंत्र और वैज्ञानिक लैंडफिल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कचरे के पहाड़ों की बायो-माइनिंग कर उनमें दबे पुराने कचरे को अलग किया जाए और भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया जाए।

जन-जागरूकता की आवश्यकता स्वच्छ भारत मिशन ने कचरा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य केवल सड़कों की सफाई नहीं, बल्कि स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, दरवाजे पर संग्रहण, पुनःचक्रण और कचरे का वैज्ञानिक निपटान है। परंतु कोई भी नीतियाँ तभी सफल होंगी, जब नागरिक उन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएँ। स्कूलों, महाविद्यालयों, आरडब्ल्यूए, बाजार समितियों और सामाजिक संस्थाओं को कचरा पृथक्करण और प्लास्टिक न्यूनीकरण के लिए निरंतर अभियान चलाने चाहिए। कचरे के पहाड़ों को हटाना केवल नगर निगम का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कचरे का पृथक्करण, पुनःचक्रण, जैविक खाद बनाना और प्लास्टिक का संयमित उपयोग ही स्थायी समाधान हैं। यदि हम आज जागे, तो कल की पीढ़ी को साँस लेने योग्य हवा, स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन दे सकेंगे।

सुशासन के संकल्प से

नवा रायपुर बन रहा

एजुकेशन हब

प्रबंधन | उद्यमिता | नवाचार

NSTI
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

NIELIT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी

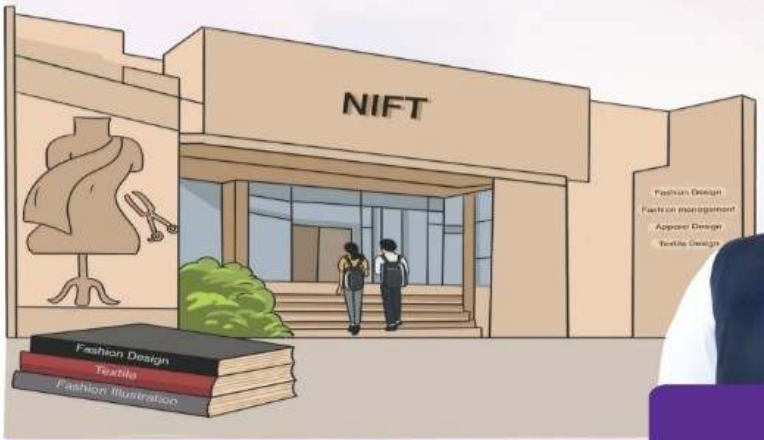
NMIMS
नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

NIFT
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी



NFSU
नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी कैम्पस

R.O. No. : 14133/ 1





श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

/ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)